## राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12217/2018

अरुण शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री त्रिपाल चंद शर्मा, आयु लगभग 39 वर्ष, भैया की पोल, घंटाघर के पास जोधपुर (राजस्थान)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सरकार के प्रमुख सचिव के माध्यम से, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, वरिष्ठ शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर।

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: डॉ. हरीश पुरोहित

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री सरवन कुमार

## माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

## <u>आदेश (मौखिक)</u>

**<u>23/04/2024</u>**

1. याचिकाकर्ता की शिकायत याचिकाकर्ता की 2015 से लंबित आवेदन के बावजूद अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने में देरी/इनकार करने के संबंध में प्रतिवादियों की ओर से निष्क्रियता के खिलाफ है।

2. संक्षेप में, मामले के प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता की मां, जो सहायक के पद पर थीं और प्रतिवादियों की सेवा करती थीं, का 22.08.2010 को सेवाकाल के दौरान निधन हो गया।

2.1 याचिकाकर्ता की बहन, मंजू शर्मा ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मांग करते हुए 23.09.2010 को एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर विचार नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने 30.09.2010 को एक और आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें अनुरोध किया गया कि उनके पहले के आवेदन को वापस लिया जाए और याचिकाकर्ता/उनके भाई को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाए।

2.2 सम्पर्क पोर्टल पर की गई शिकायत के परिणामस्वरूप प्रतिवादी क्रमांक 3 द्वारा 20.10.2015 को याचिकाकर्ता के आवेदन को स्वीकार करने के निर्देश दिए गए।

2.3. याचिकाकर्ता के आवेदन को विचारार्थ स्वीकार कर लिया गया। फिर भी, विभिन्न बहानों से याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित किया जा रहा है। इसलिए, यह याचिका।

3. याचिका के जवाब में, बचाव में यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत याचिका में कोई दम नहीं है।

3.1 याचिकाकर्ता की मां का निधन राज्य सरकार की सेवा में रहते हुए 22.08.2010 को हो गया था। हालांकि, उन्होंने 04.11.2015 को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता ने 2010 से सितंबर 2014 के बीच अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया।

3.2 दिनांक 04.11.2015 का आवेदन 1996 के लागू नियमों के तहत सीमा के कारण वर्जित है। अनुकंपा के आधार पर आवेदन प्रस्तुत करने की समय सीमा सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से 90 दिन है।

3.3 इससे पहले भी याचिकाकर्ता ने सितंबर 2014 में विधानसभा के सदस्य की सिफारिश के साथ नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। हालांकि, इसे अस्वीकार कर दिया गया था, और याचिकाकर्ता को दिनांक 11.09.2014 के पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था।

3.4 याचिकाकर्ता की बहन द्वारा याचिकाकर्ता को प्रतिस्थापित करने की मांग करने वाला दिनांक 30.09.2010 (अनुलग्नक 1) का आवेदन याचिकाकर्ता द्वारा बाद में सोचे जाने का परिणाम मात्र है। उसकी बहन द्वारा यह आवेदन डीईओ, माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर के समक्ष कभी प्रस्तुत नहीं किया गया था।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वंद्वी तर्क सुने हैं और केस फाइल का अवलोकन किया है।

5. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से तर्क दिया है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति भर्ती का स्रोत नहीं हो सकती। यह कानून की आवश्यकता का एक अपवाद मात्र है, जहां सेवा में रहते हुए किसी कर्मचारी की अचानक मृत्यु होने पर, परिवार आजीविका के किसी साधन के बिना रह जाता है। याचिकाकर्ता के विलम्बित आवेदन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मृतक कर्मचारी की मृत्यु के समय आजीविका के वैकल्पिक साधन उपलब्ध थे।

6. इस प्रकार, इस मामले में न्यायनिर्णयन का विवाद एक संकीर्ण दायरे में आता है, अर्थात क्या एक उम्मीदवार जिसने सेवा में कार्यरत कर्मचारी की मृत्यु के 90 दिनों के भीतर निर्विवाद रूप से आवेदन किया था, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मांग करते हुए, विभाग द्वारा इसे संसाधित करने में पांच साल तक की देरी के कारण अपना आवेदन वापस लेना उचित था, जिससे उसे कोई भी नौकरी पाने के बारे में पूरी तरह से निराशा महसूस हुई, इस प्रकार उसने अपने भाई को अपनी जगह देने का विकल्प चुना? 7. मेरी राय में, देरी के लिए यदि कोई दोष है, तो वह विभाग का है, तथा याचिकाकर्ता को इसके लिए प्रतिकूल परिणाम नहीं भुगतने पड़ सकते।

8. कारणों की तलाश करना बहुत मुश्किल नहीं है। आइए देखें कि कैसे।

9. याचिका में वर्णित घटनाओं तथा विभाग की प्रतिक्रिया का एक सरल विवरण यह दर्शाता है कि, विभिन्न कारणों से, याचिकाकर्ता की बहन का आवेदन चार वर्षों तक लंबित रहा, जबकि उसने राज्य की लागू नीति के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति के लिए अपनी उम्मीदवारी पर कथित आपत्तियों को दूर करने के लिए लगातार प्रयास किए।

10. इस बीच, वह विभाग के अधिकारियों द्वारा खड़ी की गई नौकरशाही बाधाओं से इतनी निराश हो गई कि, स्थिति से पूरी तरह से हार मानकर, उसने एक पत्र लिखकर सुझाव दिया कि उसके भाई, मृतक कर्मचारी के बेटे, को नियुक्ति के लिए विचार किया

जाए, बशर्ते कि वह पात्रता मानदंडों को पूरा करता हो।

11. याचिकाकर्ता द्वारा नियुक्ति के लिए देरी का रुख प्रतिवादियों द्वारा इस तथ्य की अनदेखी करके अपनाया गया है कि याचिकाकर्ता की बहन ने वास्तव में निर्धारित 90-दिन की अवधि के भीतर विभाग से संपर्क किया था। यह समझना हैरान करने वाला और परेशान करने वाला है कि याचिकाकर्ता की बहन द्वारा समय पर आवेदन प्रस्तुत करने के बावजूद, विभाग ने उसके आवेदन को पांच साल तक लटकाए रखने की अनुमति क्यों दी, और फिर याचिकाकर्ता को कथित रूप से विलंबित आवेदन के लिए जिम्मेदार ठहराया।

12. इस मामले में स्थिति उलट गई है। वास्तव में, स्थिति दूसरी तरफ है। कोई भी देरी स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता की बहन की उम्मीदवारी पर कार्रवाई करने में विभाग की विफलता के कारण है, और इस प्रकार न तो याचिकाकर्ता और न ही उसकी बहन को विभाग की अत्यधिक निष्क्रियता के लिए दोषी ठहराया जा सकता है।

13. सुनवाई के दौरान, इस न्यायालय के सुझाव पर, दोनों विद्वान अधिवक्ता इस बात पर सहमत हुए कि यदि याचिकाकर्ता की बहन वर्तमान में अनुकंपा के आधार पर विचाराधीन पद के लिए विचार किए जाने के लिए इच्छुक है, तो उसके मूल आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि यह सीमा के भीतर दायर किया गया था।

14. इसलिए, संयुक्त अनुरोध और सहमति के मद्देनजर, रिट याचिका का निपटारा याचिकाकर्ता की बहन के मूल आवेदन पर पुनर्विचार करने के निर्देश के साथ किया जाता है, जो उसकी मां की मृत्यु के बाद निर्धारित समय सीमा के भीतर दायर किया गया था। याचिकाकर्ता/उसकी बहन द्वारा इस आदेश के वेब-प्रिंट के साथ प्रतिवादियों से संपर्क करने के तीन महीने के भीतर उसे उसकी पात्रता और पात्रता के अधीन उचित नौकरी की पेशकश की जाएगी।

15. यदि याचिकाकर्ता की बहन का पिछला आवेदन विभाग द्वारा नहीं पाया जा सकता है, तो इस याचिका के साथ अनुलग्नक 2 के रूप में संलग्न आवेदन को आगे की कार्रवाई करने के लिए उसका आवेदन माना जाएगा।

**(अरुण मोंगा),** न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है )

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।